



मुद्ररीकरण की चुनौतियाँ

यह एडिटरियल 03/09/2021 को 'द हट्टू' में प्रकाशित "Is monetising public assets a good idea?" लेख पर आधारित है। इसमें हाल ही में घोषित राष्ट्रीय मुद्ररीकरण पाइपलाइन से संबंधित मुद्दों पर चर्चा की गई है और आगे की राह सुझाई गई है।

हाल ही में सरकार ने **राष्ट्रीय मुद्ररीकरण पाइपलाइन (National Monetisation Pipeline- NMP)** जारी की है जो उन विभिन्न सार्वजनिक संपत्तियों को सूचीबद्ध करने वाला एक दस्तावेज़ है जिन्हें अगले चार वर्षों में नज़ी कंपनियों को पट्टे पर दिया जाएगा।

सरकार का विश्वास है कि क्षमता से कम उपयोग की जा रही सार्वजनिक संपत्तियों के मुद्ररीकरण से सरकार को लगभग 6 लाख करोड़ रुपये प्राप्त होंगे और अर्थव्यवस्था के प्रोत्साहन के लिये नई अवसंरचनाओं के निर्माण में मदद मिलेगी। आलोचकों ने सरकार पर आरोप लगाया है कि वह मूल्यवान राष्ट्रीय संपत्तियों को 'क्रोनी कैपिटलिस्टों' के हाथ बेच रही है।

इस संदर्भ में, समग्र आर्थिक विकास पर इस योजना के दीर्घकालिक प्रभावों का मूल्यांकन करना आवश्यक हो जाता है।

राष्ट्रीय मुद्ररीकरण पाइपलाइन (NMP):

- नीति आयोग द्वारा तैयार किये गए राष्ट्रीय मुद्ररीकरण पाइपलाइन का उद्देश्य राष्ट्रीय अवसंरचना में "विकास, कमीशन, मुद्ररीकरण और नविश" के एक सुदृढ़ चक्र का निर्माण करना है।
- इसका लक्ष्य नज़ी क्षेत्र को संलग्न कर [ब्राउनफील्ड परियोजनाओं](#) में संभावनाओं को साकार करना, उन्हें राजस्व अधिकार हस्तांतरित करना (हालाँकि परियोजनाओं में स्वामित्व का हस्तांतरण नहीं) और इस प्रकार प्राप्त पूँजी को देश भर में बुनियादी अवसंरचनाओं के निर्माण के लिये उपयोग करना है।

NMP के पक्ष में तर्क:

- भारत को और अधिक बुनियादी अवसंरचनाओं की आवश्यकता है परंतु सार्वजनिक क्षेत्र के पास उसके विकास के लिये आवश्यक संसाधनों का अभाव है। इस परिदृश्य में दो संभावित प्रतिक्रियाएँ हो सकती हैं:
 - नये बुनियादी अवसंरचना के निर्माण के लिये एक संवैधानिक ढाँचे के साथ (कि उसे क्या कार्य करना है) नज़ी क्षेत्र को संलग्न करने और फिर उसके द्वारा अपने स्वयं के संसाधन जुटाने पर विचार किया जा सकता है।
 - यह समझना कि निर्माण चरण में अधिक जोखिम होते हैं और इसलिये सार्वजनिक क्षेत्र द्वारा परिसंपत्तिका निर्माण करना और फिर इसे नज़ी खिलाड़ियों को बेचना (या यदि एकमुश्त बिक्री नहीं की जाती है तो नज़ी क्षेत्र को इसका प्रबंधन सौंपना) बेहतर विकल्प हो सकता है।
- भारत सहित किसी भी देश के लिये नए बुनियादी ढाँचे के निर्माण के मार्ग में दो बाधाएँ हैं—
 - दीर्घावधिक, पूर्वानुमेय और सस्ती पूँजी तक पहुँच तथा नषिपादन क्षमता, जहाँ सरकारी एवं नज़ी एजेंसियाँ एक साथ कई प्रमुख परियोजनाओं पर कार्य कर सकती हैं।
 - इस प्रकार, NMP को बुनियादी ढाँचा क्षेत्र में सुधार को प्रोत्साहन प्रदान करने के लिये तैयार किया गया है।

NMP के लाभ:

- संसाधन वृद्धिका सृजन:** NMP सरकार को इच्छुक नज़ी पार्टियों के माध्यम से पूँजी तक पहुँच प्राप्त करने में मदद करेगा।
 - ये नविशक मुद्ररीकृत परिसंपत्तियों का रखरखाव एवं परिचालन करेंगे और नकदी प्रवाह उत्पन्न करेंगे, जबकि इसके साथ ही बुनियादी अवसंरचना क्षेत्र में प्रौद्योगिकीय एवं मानव संसाधन क्षमता का भी निर्माण करेंगे।
 - संसाधन वृद्धिका यह सुदृढ़ चक्र वार्षिक बजटीय पूँजीगत व्यय आवंटन की प्रतीक्षा किये बिना सरकार को तुरंत ही किसी नए बुनियादी ढाँचे में नविश कर सकने में सहायता करेगा।
- संपत्तिका स्वामित्व सरकार द्वारा प्रबंधित:** मौजूदा ब्राउनफील्ड, गैर-जोखिमियुक्त संपत्ति, जो चार वर्षीय मुद्ररीकरण पाइपलाइन का अंग है,

नई **ग्रीनफील्ड परसिंपत्तियों** के लिये नषिपादन क्षमता के सृजन में मदद करेगी।

◦ सरकार संपत्तियों के परिचालन और रखरखाव के अधिकारों का मुद्रीकरण कर रही है न कि उसके स्वामित्व का।

- **उचित मूल्य हस्सिसेदारी:** अनुबंधों को इस तरह से डिज़ाइन किया जाएगा कि सरकार को मुद्रीकरण से उचित वर्तमान मूल्य प्राप्त हो, जबकि निजी पार्टियों को पर्याप्त परिचालन लचीलापन और नयामक दृश्यता प्राप्त होगी।
 - इसके अलावा, चूँकि अनुबंध की शर्तें 25 वर्ष या उससे अधिक अवधि की हो सकती हैं, बोली लगाने में प्रकट रुचि से पता चलता है कि नविशक दीर्घकालिक नयामक स्थिरता और नशिचिता के प्रति आश्वस्त हैं।
- **बेहतर लक्ष्य:** NMP करदाताओं के लिये कोई नई वित्तीय देनदारी प्रस्तुत नहीं करता है यह वास्तव में एक बेहतर लक्ष्य **उपयोगकर्ता भुगतान** संरचना का प्रतिनिधित्व करता है।
 - उदाहरण के लिये, यदि दिल्ली में एक स्टेडियम का मुद्रीकरण नहीं किया जाता है तो पूरे देश के करदाता इसके रखरखाव के लिये भुगतान करेंगे। लेकिन एक मुद्रीकृत स्टेडियम के लिये भुगतान केवल दिल्ली में इसकी सुविधाओं का उपयोग करने वालों द्वारा किया जाएगा। यह परिचालन राजस्व उत्पन्न करने का एक बेहतर तरीका है।
- **सफल उदाहरण:** **भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण** (National Highways Authority of India) और **पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया** द्वारा परसिंपत्तियों मुद्रीकरण के विचार को पहले ही विभिन्न रूपों में आजमाया जा चुका है।
 - यहाँ तक कि राज्य स्तर पर भी, **मुंबई-पुणे एक्सप्रेसवे** का रखरखाव टोलिंग अधिकारों के नमित्त एक रियायतग्राही द्वारा किया जा रहा है।

संबंधित चुनौतियाँ:

- **उपयुक्त मूल्य को साकार करना:** मुद्रीकरण पाइपलाइन की पहली और प्रमुखतम आलोचना यह है कि परसिंपत्तियों से पर्याप्त मूल्य को साकार किया जा सकेगा या नहीं।
 - यह बोली प्रक्रिया की गुणवत्ता और इस बात पर निर्भर करता है कि पर्याप्त संख्या में निजी खिलाड़ी बोली लगाने के लिये आकर्षित होते हैं या नहीं।
- **बोलीदाताओं की पर्याप्त भागीदारी सुनिश्चित करना:** परसिंपत्तियों मुद्रीकरण से **क्रोनी कैपिटलिज्म** को बढ़ावा नहीं मिलेगा—यह सुनिश्चित करने का एकमात्र तरीका यह है कि बोली की शर्तों को ऐसा बनाया जाए कि यह किसी छोटे, वशिष्ट या पूर्व-निर्धारित लोगों के समूह तक सीमित न हो।
 - हालाँकि, परियोजना की पूँजी तीव्रता (Capital Intensity) के कारण हर कोई बोली लगाने में सक्षम नहीं होगा। इसके बावजूद यह सुनिश्चित किया जा सकता है कि प्रक्रिया में पर्याप्त भागीदारी हो।
- **नषिपादन जोखिम:** इतने बृहत कार्यक्रम में नशिचय ही नषिपादन जोखिम भी शामिल होगा। यद्यपि यही कारण है कि NMP 'वन-साइज़-फिट्स-ऑल' का दृष्टिकोण नहीं अपना रहा है।
- **करदाताओं द्वारा भुगतान:** एक विचारणीय विषय यह है कि चूँकि करदाताओं ने इन सार्वजनिक संपत्तियों के लिये पहले ही भुगतान कर रखा है, तो इनका उपयोग करने के लिये वे पुनः निजी पार्टी को भुगतान क्यों करें।
- **उप-इष्टतम संविदात्मक प्रवर्तन:** इस तरह की योजना की सफलता के लिये एक उप-इष्टतम संविदात्मक और न्यायिक ढाँचे को लेकर व्याप्त संदेह के कारण भी इसकी आलोचना की जा रही है।
- **एकाधिकारवादी परिप्रेक्ष्य:** कुछ प्रमुख व्यावसायिक घराने NMP के तहत प्रस्तुत की जाने वाली संपत्तियों के एक बड़े हिस्से पर कब्जा कर सकते हैं।

आगे की राह:

- **संसाधन बढ़ाने के अन्य तरीके:** एक विकास वित्त संस्था (Development Finance Institution- DFI) की स्थापना और केंद्रीय एवं राज्य बजट में अवसंरचना नविश की हस्सिसेदारी को बढ़ाने जैसे संसाधन वृद्धि के अन्य तरीके अपनाए जा सकते हैं।
- **विवाद समाधान तंत्र:** न्यायिक प्रक्रियाओं को सशक्त करने पर अधिक बल नहीं दिया जा सकता। कुशल और प्रभावी विवाद समाधान तंत्र स्वाभाविक रूप से और स्वचालित रूप से NMP के डिज़ाइन और नषिपादन में शामिल होना चाहिये।
- **सार्वजनिक-निजी भागीदारी को सुव्यवस्थित करना:** हाल के अनुभव बताते हैं कि **सार्वजनिक-निजी भागीदारी** (public-private partnerships- PPP) में अब पारदर्शी नीलामी, जोखिमों और अदायगी की स्पष्ट समझ तथा किसी भी एवं सभी इच्छुक पार्टियों के लिये एक खुला क्षेत्र शामिल है।
 - इस प्रकार, ग्रीनफील्ड परियोजनाओं में PPP की उपयोगिता की उपेक्षा नहीं की जा सकती है।
- **पारदर्शी बोली:** पारदर्शी बोली NMP परियोजना के सबसे महत्त्वपूर्ण भागों में से एक है। इस प्रकार, पारदर्शिता बनाए रखना परसिंपत्तियों मूल्य को उपयुक्त रूप से साकार कर सकने के लिये महत्त्वपूर्ण है।
- **नीति आयोग की सिफारिशें:**
 - **InvITs** को दवाला और शोधन अक्षमता संहिता (IBC) के दायरे में लाना: IBC प्रावधानों का विस्तार InvITs तक करने से ऋणदाताओं को एक तेज़ और अधिक प्रभावी ऋण पुनर्गठन और समाधान विकल्प तक पहुँचने में मदद मिलेगी।
 - **टैक्स ब्रेक्स (Tax Breaks):** कर-कुशल और उपयोगकर्ता-अनुकूल तंत्र, जैसे **InvITs** में कर-लाभों की अनुमति देना खुदरा नविशकों (व्यक्तिगत/गैर-पेशेवर नविशक) को आकर्षित करेगा।

नषिकर्ष

चूँकि वैश्विक आर्थिक परिदृश्य अस्थिर और अनशिचत बना हुआ है, अग्रिम रूप से वित्तीय संसाधनों को जुटाना एक साहसिक, रचनात्मक और आश्वस्तिकारक नीति विकल्प है। यह विश्व को संकेत देता है कि भारत सरकारी कोषागार के हितों के साथ व्यापार के लिये खुला है और नागरिकों को मज़बूती से संरक्षित किया गया है।

अभ्यास प्रश्न: 'सरकार संपत्ति के परचालन और रखरखाव के अधिकारों का मुद्ररीकरण कर रही है, न कऱसके स्वामतिव का ।' प्रस्तुत वक्तव्य के आलोक में राष्ट्रीय मुद्ररीकरण पाइपलाइन से संबद्ध मुद्दों पर चर्चा कीजयि ।

PDF Refernece URL: <https://www.drishtias.com/hindi/printpdf/challenges-of-monetisation>